# The Eazette



# of Andia

# PUBLISHED BY AUTHORITY

# No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 1963/PHALGUNA 11, 1884

#### NOTICE

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto the 19th February, 1963:-

Issue N	No. and date		Issued by	Subject
29.	No. 13(41)-W&M/62, dated 16 February, 1963.	5th Ministr	ry of Finance.	Authorising, Commissioner of India, Hong Kong, to receive subscriptions for the issue of Defence Certificates at rate of exchange stated therein.
<b>\$</b> 0.	No. 12-ITC (PN)/63, dated 18 February, 1963.	8th Ministry of C	Commerce & Industry	Import of Aluminium products under Aid Loan No. 217.
	No. 13-ITC(PN)/63, dated 18 February, 1963.	th	<b>De.</b>	Utilisation of second half of annual licences granted to Actual Users both in the Scheduled and Non-Scheduled Sectors for April, 1962—March, 1963.
	No. 1/63, dated 16th Februa. 1963.	ry,	Do.	The Imports (Control) First Amendment Order, 1963.
31.	No. 14-ITC (PN)/63, dated 19 February, 1963.	th	Dø.	Long Shoremen's strike in U.S.A.—Revalida- tion of Sub-Authorisations issued for Import of Unmanufactured Tobacco from U.S.A. under PL 480 Aid Pro- gramme against P.A. No. 39-67-O.T.

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on Indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

# **CONTENTS**

PAGES
FAGES
ction (ii).—Statutory stions issued by the Government of India latry of Defence) and ities (other than the Union Territories) 637
ory Rules and orders stry of Defence 53
cations issued by the nion Public Service say Administration,
Attached and Sub- he Government of ula)
cations and Notices of Office, Calcutta
cations issued by or o Chief Commis-
49
llaneous Notifications as, orders, advertise- issued by Statutory imla) 63
Notices by Private te bodies (Published
flee Clinibor of tuttini otification of the tuttini otification ot

### PART I-Section 1

# Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations and Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court

### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd February 1961

No. 1/5/62-ANL.—The President is pleased to constitute an Advisory Committee in respect of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands to be associated with the Chief Commissioner of the Islands.

- 2. The Advisory Committee will consist of the Chief Commissioner, who will preside over the meetings of the Committee, Member of Parliament representing the Union Territory, Senior Vice President of Port Blair Municipal Board, other non-official members of the Home Minister's Advisory Committee, Rani Chhanga of Katchall and two representatives of village Panchayats to be nominated by the Chief Commissioner.
- 3. The office of a member of the Committee shall be honorary and shall not carry any remuneration.
- 4. The Chief Commissioner will seek the advice of the Committee on matters relating to:-
  - (l) administration involving general questions of policy;
  - (ii) economic, social, cultural and educational development of the islands and welfare of the people in general;
- 5. The term of the non-official members of the Home Minister's Advisory Committee will be co-terminous with their term in that Committee and the term of other non-official members including the representatives of the Panchayats would expire on the 31st March 1964.
- 6. The Advisory Committee will meet as frequently as possible but at least once in every quarter,
- 7. Subject to the discretion of the Chief Commissioner to refuse in the public interest to give information or to allow discussion, members of the Advisory Committee will have rights in regard to interpellations analogous to and under similar limitations as those of members of a State Legislature.

A. D. PANDE, Jt. Secy.

# गृह मंत्रालय

# संकल्प

# नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1963

सं 20/16/62 ए० एक०-भारत सरकार ने निम्नीलिखित के बारें में जांच करने तथा रिपोर्ट दोने के लिए बनाए गए जांच आयोग की रिपोर्ट पर पूर्णतः विचार किया हैं:--

- (अ) वं परिस्थितियां जिनमें 10 अप्रील, 1962 को फॉनिक्स बे, पोर्ट ब्लोयर में पूलिस ने गोली चलाई,
- (आ) वह कथित गोली चलाना न्यायसंगत तथा आवश्यक भा या नहीं।
- 2. जहां तक उन परिस्थितियों का सम्बन्ध है जिनमें 10 अप्रैल, 1962 को पृत्तिस ने गौली चलाई, सरकार ने आयोग का यह मत स्वीकार कर लिया है, कि कारिन्दों ने लंबर फोर्स वर्कस के कार्य में अड़चन हाली तथा उन्हें आतंकित किया और उन्हें अपनी क्यूटी अदा करने से रोका और वह कोई शान्तिप्प धरना नहीं था।
- 3. सरकार ने यह निष्कर्ष भी स्त्रीकार किया है कि 10 अग्रेंल, 1962 को पुलिस द्वारा की गई असरदार गोलीबारी न कैवल न्याय-संगत ही थी, अपित आवश्यक भी थी, तथा उपरोक्त परिस्थितियों में पुलिस द्वारा बल प्रयोग में कोई ज्यादती नहीं थी।
- 4. आयोग द्वारा किए गए कार्य के लिए सरकार धन्यवाद दंती हैं।

आर्द्श दिया जाता हैं, कि यह संकल्प सामान्य स्चना के लिए भारत के गजट में प्रकाशित किया-जाए।

वी० विस्वानाथन, सचिव।

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

New Delhi, the 21st February 1963

No. 32(2)/63-SSI(C).—In continuation of this Ministry's notification bearing No. 21-SSI(C) (39)/59, dated the 22nd May, 1962, the President is pleased to extend the duration of the Public Works Divisions mentioned therein from the 1st March, 1963 upto and including the 29th February, 1964.

V. C. NAIDU, Under Sccy.

### (Department of Company Law Administration)

New Delhi, the 21st February 1963

No. F.8/89(293B)/62-PR.—In pursuance of sub-section (1) of section 293B of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby approves the Funds mentioned in column (2) of the Schedule annexed hereto and constituted by the Government of the State mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, as Funds to which contributions may be made for the purpose of national defence.

#### THE SCHEDULE

Sl. No.	Name of the Fund	Name of the State
(1)	(2)	)

- The Chief Secretary to the Govern- A i ra Pradesh ment of Andhra Pradesh, Hyderabad, National De ence F und.
- 2. The National Defence Fund, Andhra ra Pradesh Pradesh State Peoples' Committee.
- The Bihar State National Defence Bihar and Jawans' Welfare Fund.
- 4. The Chief Minister's Defence u d, Kerala Kerala State.
- 5. The National Defence 1 und, Madras. Madras
- The Chief Minister's Defence Services Welfare Fund, Rajasthan.
- The Chief Minister's Defence Forces Uttar Pradesh Welfare Fund, Lucknow.
- The Chief Minister's Defence Pur- U: ar Pradesh poses Fund of Uttar Pradesh, Lucknow.
- The Chief Minister's West Bengal West Bengal Account National De ence Fund.

F. N. SANYAL, Under Secy.

# वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग)

# संकल्प

नर्ड दिल्ली <sup>15</sup> अक्त्<sub>बर</sub>, 1962

सं० 6(8) टंक्स (ग)/62-लण्ड 2.—भारत सरकार ने मद्रास भें एक हथकरचा माल निर्यात संवर्धन सलाहकार समिति गठित करने का विनिश्चय किया है। इस समिति के कृत्य इस प्रकार होंगे:—

(क) भारत सरकार, इधकरघा बोर्ड तथा निर्यात में हित रखने वालों के बीच संचार माध्यम के रूप में कार्य करना जिससे उन समस्याओं पर सुगमता से विचार विमर्श किया जा सके जिनका कि समस्त प्रचेत्र और किस्मों के इथकरघा कपड़ों के निर्यात को सामना करना पड़ता हैं,

- (स्त) परम्परागत और अपरम्परागत दोत्रों में इथकरचा कपड़ीं के निर्धात को बढ़ाने के सर्वोत्तम उपायों और तरीकों को बार में सिफारिशों करना,
- (ग) इथकरघा कपड़ा अभिनिर्माताओं में समृत्र पार के देशों में विक्री बढ़ाने में दिलचस्पी पेंदा करना,
- (ध) वस्त्र तथा नकली रेशम निर्यात संवर्धन परिषद और हथकरचा कपड़ों तथा हथकरचा मालों का निर्यात बढ़ाने से सम्बन्ध रखने वाले देश के अन्य निकायों के साथ निर्यात संवर्धन के मामले में निकट सम्पर्क बनाये रखना,
- (ड०) निर्यात बढ़ाने की धीष्ट से निर्यात संवर्धन प्रोत्साहन क ह्म और प्रकार तथा निर्यात सम्बर्धन थोजना/योजनाओं के क्रियाचालन और उनके परिपालन के बार में सरकार को सलाह दोना,
- (च) असिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, असिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विपणन सहकारी संस्था हस्तशिल्प तथा हथकरघा विकास निगम तथा निर्यात में लगी हुई अन्य सहकारी संस्थाओं जैसी जो विभिन्न संस्थायें हस समय काम कर रही हैं उनके और सब हथकरघा निर्यातकों के बीच समस्त प्रक्षेत्र और किस्मों के हथकरघा माल के निर्यात के सम्बन्ध में समन्वय स्थापित करना।

यद्यपि उपरोक्त विषय पर सिफारिशों करना समिति का कार्यं होगा तथापि यह अधिक समीचीन होगा कि वे सिफारिशों विदेश स्थापार सम्बन्धी उन सामान्य नीतियों के संगत हों जो समय समय वर भारत सरकार द्वारा निधिरित की जाएं। समिति का गठन

## अध्यक्त

1. वस्त्रायुक्त और अध्यक्ष, अखिल भारतीय हथकरघा बार्ड

# **उपाध्य**च्

- 2. आयात तथा निर्यात को संयुक्त मुख्य नियंत्रक, मद्रास
- 3. श्रीमसी पुपुल जयकर, अर्वतिनिक सलाहकार (हथकरचा), बस्बर्ड
- 4. प्रधान, अखिल भारतीय हथकरघा कपड़ा विषणन सहकारी संस्था लि०
- श्री बीठ सीठ श्रीरामुल, चंद्दी, एसठ बीठ एसठ ट्रीडंग कंठ, महास
- 6. श्री एम० पी० नाचिम्तु मुद्गीलयार, प्रधान, तीमलनाड हथकरचा ब्नकर सहकारी संस्था, मद्रास
- 7. श्री एम० एस० ए० मजीद, प्रधान, हथकरघा वस्य अभिनर्माता संस्था, महास
- 8. महाप्रबन्धक, हथकरघा निर्यात संगठन, मद्रास
- 9. श्री एल० पी० गुप्ता, मार्फत/इंस्थिन टेक्सटाइल्स कं० लि०, कलकता/बाराणसी
- 10. श्री लद्दमीनारायण, जनार्दन सिल्क हाउस, बंगलौर
- 11. श्री सी० पी० कृष्णन नायर, कन्नान्र, करल
- 12. इधकरचा निदंशक, मद्रास
- 13. हथकरचा निवंशक, आधू प्रदेश,
- 14 श्री एम० एस० रामनाथ, निर्देशक, अखिल भारतीय हथकरधा बोर्ड, बम्बर्ड
- 15 श्री मलप्पा कोल्ल्र, वंगलॉर
- 16. श्री एन० पी० गांधी, सदस्य, इथकरघा बोर्ड

17. श्री आरु गोविन्दराजा चंद्दी, अधंतिनक सचिव, सेलम हथकरघा वस्त्र अभिनिर्माता सथा निर्मातक संस्था, सेलम

अध्यस्न, हथकरघा कपड़ा आँर हथकरघा माल के निर्चात से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों को भी अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेगा।

समिति को हथकरघा कपड़ा और हथकरघा माल के निर्यात का विकास करने से सम्बन्धित विशेष समस्याओं अथवा समस्या संवर्ग को सुलभाने के लिए उप-समितियां और विशेषज्ञों के पेनल नियुक्त करने की शक्तियां होगी।

समिति का माम्ली तार पर मास में कम से कम एक अधिवेशन होगा । महास स्थित वस्त्राधुक्त का म्रीत्रीय कार्यालय, समिति को साचिविक सहाथता देगा ।

समिति दो वर्ष की कालावीध के लिए बनायी आएगी।

# आवृश

आदेश दिया गया कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सब सम्पृक्त राज्य सरकारों, पांडिचेरी के मूख्यायुक्त आदि आदि को भंजी जाये।

यह भी आईशा दिया गया कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के गजट में प्रकाशित किया जाए।

ही० के० श्रीनिवासाचार, संयुक्त सचिव।

# MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

#### RESOLUTION

New Delhi, the 19th February 1963

No. F.103(2)/62-DWI.—In this Ministry's Resolution No. F. 11(2)/54-DW.I, dated the 14th April, 1935, (as amended from time to time), constituting the Chambal Control Board, the following additional entries may be made under para 3 after the entry number (xii):—

# Members

- (xiii) Chalrman, Madhya Pradesh Electricity Board, or his representative.
- (xiv) Chairman, Rajasthan State Electricity Board, or his representative.

# Order

Ordered that this Resolution be communicated to the State Governments of Rajasthan and Madhya Pradesh, the Ministry of Finance and the Planning Commission.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Madhya Pradesh and Rajasthan be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

B. K. UPPAL, Dy. Secy.

# सिचाई व विजली मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1963

# संकल्प

सं० एफ० 103(2)/62-ही० हमस्यु० 1.—इस मंत्रालय के समय-समय पर यथा-संशोधित संकल्प संख्या एफ० 11(2)/54-ही० हरून्य्-1 तारीख 14 अप्रेंल, 1955, जिसके द्वारा चम्बल कन्द्रोल बोर्ड की स्थापना हुई थी, के पैरा  $^3$  के नीचे, इन्दराज संख्या ( $^{12}$ ) के बाध, नीचे-सिस्स इन्दराज किए जाएं:—

# सन्स्य

(13) अध्यद्भ, मध्य प्रदेश विजली बोर्ड, या उनके प्रीतिनिधि।

(14) अध्यक्त, राजस्थान राज्य विजली बोर्ड, या उनके प्रति-निधि।

#### आवंश

आयेश दिया जाता हैं कि इस संकल्प की एक-एक प्रीत राजस्थान और मध्य प्रदंश के राज्य सरकारों/वित्त मंत्रालय व योजना कमीशन को भेज दी जाए।

यह भी आर्दश दिया जाता हैं कि यह संकल्प भारतीय राजपम में छ्यं और कि मध्य प्रदेश व राजस्थान की राज्य सरकारों से प्रार्थना की जाए कि वे इसे जन-साधारण की जानकारी के लिए राज्यों के राजपन्नों में छापें।

बी० के० उप्पल, उप-सचिम।

# New Delhi, the 21st February 1963

No. EL.II-12(21)/61.—In this Ministry's Resolution No. EL. II-12(21)/61, dated the 26th September, 1962, relating to the constitution of the Control Board for the installation of 3 sets of 50/62.5 MW each at Delhi, for entry (2) under paragraph 2, the following shall be substituted:—

 Shri M. S. Ram, Officer on Special Duty, Ministry of Irrigation and Power-Member.

#### Oungu

Ordered that the Resolution be communicated to the Government of Punjab, the Delhi Administration, the Delhi Municipal Corporation, the Punjab State Electricity Board, the Ministries of Home Affairs and Finance, Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for information,

M. K. KIDWAI, Jt. Secy.

# MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT RESOLUTION

# New Delhi, the 16th February 1963

No. WB-16(30)/62.—The Central Wage Board for the soul mining industry, set up by the Government of India by their Resolution No. WB-16(1)/62, dated the 10th August, 1962, has considered the question of interlin wage increase for workmen, as required by Para 3(c) of the resolution, and has made recommendations as shown in the Schedule attached.

2. The Government of India have decided to accept these recommendations of the Wage Board and to request the concerned employers to implement the same as early as possible.

# Order

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the interests concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information,

# SCHEDULE

# Recommendations of the Central Wage Board for the Coal Mining Industry

(i) An interim wage increase, over the existing wages, of 37 nP. per day's attendance to the daily rated (time-rated and piece-rated) workmen (including miners' sirdars and other working sirdars) and of Rs. 9.73 nP. per month to the

monthly paid workmen in the collieries and in their following ancillary undertakings, departments, offices and establishments

- (a) Bye product coke plants.
- (b) Beehive and country ovens/Bhattas.
- (c) The manufacture of soft coke,
- (d) Captive power stations, i.e. those run by collieries themselves for their own use.
- (e) Central or Regional Workshops belonging to collieries or groups of collieries i.e. those owned by coal companies.
- (f) Washeries belonging to individual coal companies.
- (g) Stowing, i.e. sand-gathering plants situated at sources of sand supply.
- (h) Central and other ropeways, tramways and private railways belonging to coal companies.
- (i) Central stores which are owned by coal companies.
- (j) Watch and Ward and/or Security Departments.
- (k) Zemindary offices.
- Central hospitals and medical establishments belonging to coal companies.
- (m) The offices and establishments of Chief Mining Engineers, Colliery Superintendents and other officers situated in the coalfields.
- (n) Canteens.
- (o) Educational institutions, including teachers directly employed or paid by the colliery managements.
- (p) C.R.O. Establishments.

This interim wage increase shall also apply to all workers and staff engaged through or by contractors in all processes directly connected with the raising and despatch of coal and manufacture and despatch of coke.

- (ii) This interim wage increase shall be granted with effect from 1st March, 1963.
- (iii) Those monthly rated workers of the National Coal Development Corporation who have opted for the Central Pay Commission scales of pay will not be entitled to the benefit of this interim wage increase.
- (iv) The recommended interim wage Increase will also count for the purposes of the following benefits only:—
  - (a) Contributions to provident fund.
  - (b) Workmen's Compensation or Insurance.
  - (c) Overtime.
  - (d) Leave with pay.
  - (e) Paid festival holidays.
  - (f) Maternity leave and sick khoraki/leave.
  - (g) Lay-off and retrenchment compensation payments.
  - (h) Gratuity, pension and other retirement benefits, wherever they exist, and which may be paid on or after 1st March, 1963.
- (v) The interim wage increase will not count for calculation of dearness allowance or bonus under the Coal Mines Bonus Scheme.
- (vi) The interim wage increase shall be without prejudice to any subsequent increases in the quantum of dearness allowance to which the workmen may become entitled under the scheme of variable dearness allowance awarded by the Decision dated 29th January, 1987 of the Labour Appellate Tribunal of India, which scheme is in force at present.
- (vii) These recommendations are only interim and made without prejudice to the final recommendations to be made by the Board. The Board, therefore, further recommends that the amounts paid to the workmen under this interim wage increase will be specified separately till the final recommendations are made by the Board, after which such final recommendations shall prevail.

P. M. MENON, Secy.